मजबूरन पुलिस को दर्ज करना पड़ा मुकदमा

फ़रीदाबाद, (म.मो.) । 1-15 अक्तूबर के अंक में 'हाईकोर्ट जाए भाड़ में अवैध निर्माण तो यूं ही चलेंगे' (शीर्षक) नाम से खबर छापी थी। जिसको लेकर थाना एन आई टी पुलिस ने न चाहते हुए भी बिल्डर विक्की उर्फ़ चाँद पर पूरी रियात करते हुए मुकदमा न. 238भारतीय दण्ड संहीता की धारा 188 मात्र लगाकर मामला दर्ज कर ही दिया व कच्ची जमानत लेकर उसे साथ ही साथ छोड़ भी दिया। इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी व आई ओ कैलाश ने अपनी कलम का पूरा-पूरा इस्तेमाल करते हुए 5सी/44 शॉपिंग काम्पलेक्स के मुख्य मालिक व अन्य पार्टनरों पर कृपा दृष्टि बनाते हुए सिर्फ़ चांद को ही बलि का बकश्रा बनाया।

सुधी पाठकों ने मज़दूर मोर्चा के 1-15 जून के अंक में पढ़ा होगा कि किस तरह नगर-निगम अधिकारियों व पार्षद पति नरेश गौसांई ने बिल्डर चाँद व उसके पार्टनर नरेश आहूजा से एक मोटी रकम लूट-कमाई करके 5सी/44 काम्पलैक्स में अवैध निर्माण बनाने के लिये प्रोत्साहित किया। नगर-निगम अधिकारियों व जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदो से सैटिंग होने के बाद बिल्डरों ने नगर-निगम द्वारा सील की गई 5सी/44 काम्पलैक्स में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी रखा।

इस पूरी लूट कमाई को भी मज़दूर मोर्चा ने 1-15 जून के अंक में प्रकाशित किया था। जिस पर निगम अधिकारियों को मजबूर होकर पहले से ही सील बिल्डिंग को दोबारा सील करना पड़ा। 5सी/44 बिल्डिंग को जुलाई 2013 में पहली बार सील किया गया था। उस वक्त सिर्फ़ पहली मंजिल पर काम चल रहा था। जब दूसरी बार सीलिंग की गई उस वक्त दूसरी मंजिल स्थित दुकानों की छत ढल चुकी थी। आज स्थिति ये है कि शॉपिंग काम्पलैक्स तैयार खड़ा है।

थाना एन आई टी पुलिस ने जो मुकदमा न. 238 बिल्डर चाँद पर दर्ज किया है। सुत्रोंनुसार उसमें जिक्र किया है कि मुखबर खास से पता चला कि 5सी/44 शॉपिंग काम्पलैक्स में अवैध निर्माण चल रहा है। जबकि मुकदमा दर्ज होने से लग-भग 15 दिन पहले ही थाना एन आई टी प्रभारी को 5एल/ब्लॉक निवासी ने एक लिखित शिकायत देकर 5सी/44 व अन्य अवैध निर्माणों की जानकारी दी थी। जिस पर थाना एन आई टी प्रभारी ने ए एस आई जगबीर सिंह को मौका-मुआयना करने भेजा था, उसी शाम 5 नम्बर के भू-माफ़िया चांद को लेकर थाना एन आई टी पहुंचे थे व एक लिफ़ाफ़ा थाना प्रभारी को देकर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया था।

5 नम्बर शिव मंदिर रोड पर स्थित एक ज्वेलर ने बिल्डरों से एक मोटी रकम लेकेर थाना प्रभारी के कहने पर एन आई टी के ए सी पी को भी पहुंचाई थी। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि जुलाई 2013 से लेकर 2 अक्टूबर तक थाना एन आई टी पुलिस का मुखबर खास कहां घास काट रहा था? वहीं दूसरी तरफ़ इतना सब होने पर क्या निगम कमिश्नर यह कह सकती है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि शहर में कैसी लूट मची है। या कह सकती है कि पता तो उनको भी है पर वे क्या करें उनकी कोई सुनता नहीं सारे का सारा महकमा ही बिगड़ा हुआ है। अकेले क्या करें? यदि वे ऐसा कहती है तो वे इस पद के लायक ही नहीं है। हां वे ये जरूर कह सकती है कि जब संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लूटने में जुटे हुए है, तो उन्होंने ही कौन से पाप कर रखे हैं जो लूट कमाई को छोड़ कर खामखा की पंगेबाज़ी में पड़े ।

भाजपा चेहरा व चरित्र

फरीदाबाद 10 अक्तूबर। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र अभी तक कोई नहीं जान पाया है। इस मामले में कांग्रेस और दूसरे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल अंधेरे में हैं। हालांकि ये भाजपा पर साम्प्रदायिक होने का राग अलापती रहती है पर कई मुखौटों के भीतर छीपे असल चेहरे को जनता के सामने नहीं ला पाये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो पार्टी को समय क्षेत्र और जातियों के आधार पर प्रयोग करने के नये तौर तरीके इस्तेमाल किये हैं।

अपने साम्प्रदायिक एजेन्डे को लेकर आगे बढती दिख रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर अनेक ऐसी योजनाएं खदबदा रही है जो ऊपरी स्तर पर नज़र नहीं आती। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने या तो इसका नोटिस नहीं लिया या फ़िर वे इस मामाले में अनजान है। भाजपा छद्म वेष में जो कर रही है। वह अभी महसूस नहीं हो रहा है। पर इसके दूरगामी नतीजे होने हैं।

इन्हीं नीतियों के तहत भाजपा ने समाज को धर्म के अलावा जाति क्षेत्र और धड़ों में बांट दिया है। नतीजतन अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से भाजपा पूर्ण बहुमत से केन्द्र में है। भारतीय जनता पार्टी में साम्प्रदायिकता का नकाब ओढ कर देश में हिंदू समाज का भी कहीं भाषा के नाम पर कहीं जाति के नाम पर और कहीं क्षेत्र के नाम पर आपस में टकराव करवाया।

मसलन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर प्रवासियों को मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ने के लिये हिंसक आन्दोलन पर उतर आती है तो दिल्ली में सत्ता हथियाने के लिये इसी भाजपा को प्रवासी प्यारे लगते हैं और प्रवासियों को गले लगाते हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा यादवों को निशाने पर लेती है पर हरियाणा में यादवों के सहारे सत्ता पाने के सपने देखती है। उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिये साम्प्रदायिक दंगे करवाती है और जाटों को आगे कर यादवों और मुसलमानों से टकराव बनाती है। यही भाजपा यू पी के जाटों के सहारे आम चुनाव फतह करती है पर हरियाणा में जाटों के ख़िलाफ़ दूसरी जातियों को लामबंद कर रही है। प्रदेश में जाट गैर जाट का जहर भाजपा ने घोल दिया है और कई जगहें इसके असर भी नज़र आने लगे हैं। राजस्थान में अपने फ़ायदे के लिये जाटों की हिमायती बनकर जाट राजपूत गठजोड़ के जरिये प्रचण्ड बहुमत पाती है। यहां गुजरों को अलग-थलग कर उनके वाजिब हक भी उन्हें देने से गुरेज करती है पर हरियाणा में गुजरों की बड़ी हिमायती बनने का स्वांग रचती है।

भाजपा महाराष्ट्र में मराठा कार्ड खेलती है। बिहार में भाजपा को नीतिशकुमार का अतिदलित समाज को ऊपर उठाना अखरता है। भाजपा यहां उच्च वर्ग के सवर्ण समाज की पैरवीकार है। पिछड़े और दलित उसके निशाने पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मायावती की दलित राजनीति नहीं भाती और बसपा के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की नीति को सहन नहीं कर पाते। छत्तीस गढ़ और झाड़खंड में भाजपा आदिवासियों की आड़ में नक्सली चेहरों को बढ़ाती है।

हरियाणा में जाटों को निशाने पर रखकर भाजपा जाट नेताओं के सहारे चुनाव तो जीतना चाहती है पर किसी भी जाट को मुख्यमंत्री बनाने का एलान नहीं करते। प्रदेश में भाजपा किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी पहले ही कर चूकी है। मोदी हरियाने का डंका दूनियां में बजाना चाहते हैं पर इसकी कीमत प्रदेश के लोगों को आपसी भाईचारा खो कर चुकानी पड़ेगी।

झूठे नेताओं के झूठे शपथ पत्र और अंधा चुनाव आयोग

फरीदाबाद (म.मो.)। चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ समय पहले एक शपथ पत्र दायर करने का फैसला लिया गया, ताकि जनता यह जान सके कि वह जिस प्रत्याशी को वोट देने जा रही है, उसका व्यक्तिगत चरित्र क्या है? उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है? उसकी आर्थिक हैसियत क्या है? परिवार की आर्थिक हैसियत क्या है? इसका ब्यौरा राजनेताओं को अपने शपथ पत्र में देना होता है। व्यवस्था यह भी है कि जो उमीदवार शपथ पत्र में गलत जानकारी देगा, चुनाव आयोग उसका नामांकन रद्द कर सकता है, लेकिन शपथपत्र को लेकर हमारे उमीदवार कितने सच्चे हैं, इसके लिए हमने कुछ उमीदवारों के शपथपत्र की पड़ताल की। सच्चाई यह है कि शपथपत्र में उमीदवार केवल घोषित संपत्ति का ब्यौरा ही देते हैं, लेकिन घोषित संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उससे हमारे जनप्रतिनिधियों का झूठा चेहरा बेनकाब हो सकता है, परंतु चुनाव आयोग इसे देख कर भी अनदेखा कर देता है। करे भी क्यों न, बतौर चुनाव अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी इन शपथ पत्रों पर अंगुली उठा सकता है, वे किसी न किसी तरह इन नेताओं से लूट का हिस्सा जो लेते हैं, फिर उन्हें यह भी पता है कि यदि वह नेता जीत गया तो फायदा तो उनका ही होना है, इसलिए अधिकारियों के पास पड़ताल तक का समय नहीं होता।

शिवचरण का झूठ

हरियाणा के राज्य मंत्री की मौज लूट चुके शिवचरण लाल शर्मा ने किस तरह शपथ पत्र में झूठ लिखा, इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि पांच साल पहले सितंबर 2009 में शिवचरण लाल शर्मा ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग में जमा कराया था, उसमें शर्मा की उम्र 65 साल लिखी थी और अब यानी सितंबर 2014 में पांच साल बाद जो शपथ पत्र जमा कराया है, उसमें शर्मा की उम्र 80 साल हो गई है। पांच साल में शर्मा ने अपनी धन दौलत तो कई गुणा बढ़ाई होगी, लेकिन उम्र भी तीन गुणा बढ़ा दी। शिक्षा के मामले में भी शर्मा महान हैं। पांच साल पहले शर्मा की शिक्षा मिडल क्लास थी तो अब दसवीं फेल हो गई है।

जहां तक धन दौलत की बात है तो वो तो पांच साल पहले भी शर्मा के पास कम नहीं थी। पंडित जी के पास जवाहर कालोनी में चार मकान है, जिसे जोड़ कर एक बना लिया है। यह कुल 430 वर्ग गज के हैं। अगर बाजार भाव की बात करें तो इसकी कीमत कम से 1.70 करोड़ रुपये है, लेकिन शपथ पत्र में इसकी कीमत एक तिहाई यानी 67 लाख रुपये दिखाई है। वह भी पंडित जी ने अपनी पत्नी के नाम दिखाई है। खुद के नाम तो केवल जेवर उत्तरप्रदेश में 90 गज का मकान ही है, जिसकी कीमत 6.50 लाख रुपये ही है। हां, पांच साल पहले तक जवाहर कालोनी के तीन मकान पंडित जी के नाम पर ही थे। इनमें से एक तो 733 वर्ग गज का था, जिसका जिक्र इस बार के शपथ पत्र में नहीं है। हो सकता है कि अपने बेटों के नाम कर दिया हो। आखिर, बाप बेटों के लिए ही तो कमाता है।

शपथपत्र में तो बेटे-बेटियों के नाम जो संपत्ति है, उसका भी जिक्र करना होता है, लेकिन यहां पंडित जी कह सकते हैं कि तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं, आश्रित नहीं हैं, इसलिए उनकी संपत्ति का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, परंतु सही मायने में तो ये तीनों बेटे पंडित जी के ही आसरे हैं और इन तीनों की संपत्ति भी शपथ पत्र में लिखी होती तो शहर के लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि पंडित जी कितने धनी हो चुके हैं।

महेंद्र प्रताप

जिले के एक और मंत्री हैं महेंद्र प्रताप सिंह। पढ़े लिखे हैं। इसलिए बारीकी से काम करते हैं। पांच साल पहले महेंद्र ने जो शपथपत्र जमा कराया है, उस समय उनकी सैनिक कालोनी, सेक्टर 49 वाली कोठी का साइज 2000 वर्ग गज था, लेकिन अब वह साइज बढ़ कर 7000 वर्ग गज हो गया है और पांच साल पहले उनकी कोठी की कीमत 1.80 करोड़ रुपये थी, यानी कि 9000 रुपये वर्ग गज। जो अब बढ़ कर 35 करोड़ रुपये हो गई है। यानी कि 50 हजार रुपये वर्ग गज है। और अगर आप बाजार भाव पूछने जाएं जो वहां 90 गज के लैट की कीमत 35 लाख रुपये से कम नहीं है। ध्यान रहे, हम फ़्लैट की बात कर रहे हैं कोठी की नहीं।

यह तो केवल उदाहरण ही हैं। इन दोनों मंत्रियों के शपथ पत्र को ध्यान से देखें तो इसमें कृषि भूमि की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जिनकी कीमत बाजार भाव से काफी कम दिखाई गई है। ऐसे में सवाल यह है कि जब झूठे नेताओं के झूठे हलफनामे लेने की रस्म अदायगी क्यों की जा रही है? चुनाव आयोग वाकई चाहता है कि उमीदवार पूरी जानकारी जनता को दे तो क्यों नहीं कोई ऐसी कार्रवाई करता, जिससे नेताओं के होश ठिकाने आ जाएं और कम से कम शपथ पत्र तो सच्चा भरें।

परीक्षा में फ़ेल होकर सड़कों पर उतरते छात्र

फ़रीदाबाद, गुड़गांव (म.मो.) आजकल एक सामाजिक चलन हो गया है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिये सड़कों पर जाम लगा दिया जाये। जितनी बड़ी सड़क व भारी जाम होगा उतनी जल्दी सरकार व प्रशासन हरकत में आते हैं, वरना कोई सुनने वाला नहीं।

इस पखवाड़े राजकीय महिला कॉलेज फ़रीदाबाद की 86 में से 80 छात्रायें एम डी यू ने एक परीक्षा में फ़ेल घोषित कर दीं। फ़ेल भी इस बुरी तरह कि किसी के ज़ीरो अंक तो किसी के 2,4 आदि यानी सभी 10 अंकों से नीचे-नीचे। कॉलेज में हंगामा हुआ तो संवेदनहीन व ग़ैरजिम्मेदारी का परिचय देते हुए प्रिंसिपल महोदया ने छात्राओं को कॉलेज से बाहर जाने को कह दिया। छात्रायें बाहर आकर राजमार्ग पर बैठ गयीं।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाया व आश्वस्त किया कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करा दी जायेंगी। वे मान गयीं और प्रिंसिपल की बेवकूफ़ी से बिगड़ी समस्या का समाधान हो गया।

दो दिन बाद लगभग ऐसी ही समस्या राजकीय महिला कॉलेज गुड़गांव में भी उठ खड़ी हुई। वहां तुरन्त समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने छात्राओं को न केवल आवश्वस्त किया बल्कि दो दिन के भीतर यूनिवर्सिटी से उत्तर पुस्तिकायें मंगा कर छात्राओं व विशेषज्ञों के सामने जांच करवा दी गयीं। परीक्षापरिणाम में घोषित किये गये सभी अंक ठीक पाये गये। यानी जिन्हें फ़ेल और बुरी तरह से फ़ेल किया गया वे उसी लायक थीं। लेकिन यह अधूरा सच है। ये छात्रायें पैदायशी नालायक नहीं हैं। इन्हें शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था ने न केवल नालायक बनाया है बल्कि बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है।

एन सी आर, खासकर फ़रीदाबाद व गुड़गांव के तमाम सरकारी कॉलेजों में वे छात्र-छात्रायें दाखिला लेते हैं जो दिल्ली या अन्य कहीं अच्छे संस्थानों में दाखिला नहीं ले पाते। खोजबीन करने पर यह तथ्य भी सामने आया है कि इन सरकारी कॉलेजों में 95 प्रतिशत छात्र-छात्रायें हरियाणा बोर्ड से 12 वीं पास करके आते हैं। सी बी एस ई द्वारा पास बच्चे तो इन कॉलेजों की तरफ़ झांकना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इनका माहौल, वातावरण, शिक्षण व्यवस्था एवं संस्कृति उसके बिल्कुल विपरीत है जो वे अपने स्कूलों में से छोड़ कर निकले होते हैं।

विदित है कि हरियाणा सरकार के तमाम सरकारी स्कूल हरियाणा शिक्षा बोर्ड से ही सम्बन्धित हैं। इन स्कूलों का हाल इतना बेहाल है कि सी बी एस ई के तयशुदा मानकों पर खरे उतर ही नहीं सकते, इसलिये इन्हें सी बी एस ई की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे में इन स्कूलों को मान्यता देने के लिये हरियाणा बोर्ड ही बचता है। इन सरकारी स्कूलों के अलावा वे प्राइवेट स्कूल भी इस हरियाणा बोर्ड से मान्यता पाते हैं जो सी बी एस ई के मापदंड़ों पर खड़े नहीं उतर सकते। सरकारी स्कूलों में पढने-पढाने की समुचित व्यवस्था न होने के बावजूद, सरकार अपनी साख बचाने और शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिये येन-केन-प्रकारेण 'बढिया' परीक्षा परिणाम दिखाने को मजबूर हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल अपना व्यवसाय चमकाये रखने के लिये यही सब कुछ करते हैं।

इसका सबसे सरल तरीका है नकल। बड़े पैमाने पर नकल। सामूहिक नकल। एक ओर तो सरकार नकल रोकने की नाटकबाज़ी पर भारी खर्च करके अतिरिक्त चैकिंग स्टाफ़, पुलिस व मैजिस्ट्रेटों को तैनात करती है जो परीक्षा स्थलों पर जा-जा कर खूब भिड़ते हैं, अच्छी खासी सिर फुटैव्वल होती है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा स्टाफ़ में तैनात होने के लिये बड़े पैमाने पर पैसे का लेन-देन होता है। तैनाती के बाद फ़िर यह स्टाफ़ नकल कराने के पैसे परीक्षार्थियों से वसूलता है। कई मामलों में पैसों के बदले यौन शोषण से भी काम चलाया जाता है। जाहिर है इस तरह से परीक्षा पास करने वाले कहीं तो अटकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे काग़ज की नाव में सवारों का डूबना तो तय होता है।

इस बिगड़ी हुई शिक्षणा व्यवस्था का शिकार केवल वे साधन विहिन लोग ही बन रहे हैं जिनके पास महंगे (सी बी एस ई) सकूलों में फ़ीस के नाम पर 50 से 60 हज़ार (वार्षिक) प्रति बच्चा देने को नहीं हैं और वे इन सरकारी बाड़ों में बैठने को अभिशप्त हैं। पूरी शिक्षण व्यवस्था विशेषकर सरकारी बाड़ों की यह हालत कोई 5 या 10 साल में नहीं हो गयी है। पिछले 50 सालों से सरकार चलाने वाले तमाम गिरोहों की कुटिल नीतियों का परिणाम है यह। वरना इससे पहले तमाम सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आम जनता को उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का एक सस्ता व सुलभ साधन होते थे, जिन्हें इन सरकारों ने पूर्णतया नष्ट कर दिया है।

कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सिथति भी कोई बहुत अच्छी नहीं रह गयी है। शिक्षा बजट में बचत के नाम पर अब सरकार नियमित प्रोफ़ेसरों की जगह दिहाड़ीदार प्रोफ़ेसरों को रखने लगी है। इन प्रोफ़ेसरों को साल भर में इतना वेतन भी नहीं मिलता जितना पक्के प्रोफ़ेसर एक माह में ले लेते हैं इसके अलावा और तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां सरकार ने बना छोड़ी हैं जिनसे पढने-पढाने का माहौल ही तहस-नहस होता जा रहा है।